PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, the hon. Member should be, on the contrary, very happy to know that though the total cost of the project is Rs. 7 crores, within one year itself, we have allotted Rs. 1 crore, which is the maximum percentage of allocation for a single line. In one year, we do not spend more than Rs. 1 crore at all. Then, he wanted to know when the work will be started. I am very happy to announce that I will be visiting Kerala on the 14th or 16th of April when I will be inaugurating the construction work in respect of the Alleppey-Ernakulam railway line and I hope he will offer me the necessary hospitality.

MR. CHAIRMAN: There is no second supplementary. Next question.

Government grants for Family Welfare Programme

*63. SHRI KISHAN LAL SHARMA:†
SHRI LEONARD SOLOMAN SARING:
SHRI SYED NIZAM-UD-DIN:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of the private institutions receive grants from Government under the Family Welfare Programme for family planning activities;

(b) if so, what is the name of the agency through which this grant is paid to these institutions, and what are the conditions and mode of payment; and

(c) whether Government have received any complaints from some private institutions regarding non-payment of such grants; if so, what action Government propose to take thereon?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kishan Lal Sharma.

THE MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RABI RAY): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is placed on the Table of the Sabha.

(c) Some complaints have been received from private organisations regarding delay in release of grant-in-aid. The procedure for release has subsequently been simplified in consultation with the State Governments and the recommendations of the Conference of Voluntary Organisations held in May, 1978.

Statement

The role of private institutions in the Family Welfare Programme had been recognised from the very inception of the Family Welfare Programme and financial assistance was made available to them directly from the Central Government. Subsequently to speed up the process of release of grants to private institutions, the State Governments were delegated powers to sanction grants-in-aid to private institutions upto a limit of Rs. 1 lakh in a year in each case. In each State/Union Territory a State Grants Committee was formed to consider the applications for grants to private institutions and local bodies. Instructions were given to the effect that the grants-in-aid committee should meet as often as necessary and at least once in a quarter. As already stated the State Grants Committee could consider applications for grants upto a limit of Rs. 1 lakh in a year. This power has recently been enhanced to Rs. 2.5 lakhs in each case for all ongoing approved schemes as per pattern. Instructions were also issued for the formation of a District Level Grants Committee in each State by way of further delegation of powers. This Committee could consider applications for grants received at its own level upto a limit of Rs. 7,500.00 per annum.

Proposals for grants-in-aid above the limit of Rs. 2.5 lakhs per annum

in each case are required to be sent to the Department of Family Welfare, Government of India for administrative approval, by the State Government with their recommendations.

At present financial assistance is available from the Government to private institutions for the following schemes as per pattern:—

(i) Urban Family Welfare Centres

(ii) Sterillisation Beds Scheme

(iii) All India Hospital Post Mortum Programme

(iv) ANM Training Schools.

The Government of India provides financial assistance directly to 18 Population Research Centres located all over India for undertaking demographic and communication action research activities. As the scope of activities of such centres frequently extends beyond the margins of any single State, financial assistance to such centres is provided by the Government of India directly.

Apart from the above instances where grants are made available to private institutions as per pattern prescribed by the Central Government such institutions are also encouraged to undertake experimental projects in such aspects of the Family Welfare Programme such as services, training, communication, motivation, education, research and other such innovative activities. Funds for such experimental innovative projects are provided to institutions directly by the Government of India.

श्री किशन लाल शर्मा : महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं मिला है। मैंने उन संस्थानों के नाम का जिक्र किया था जिनका नाम स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अनुदान समितियों का गठन करने के लिये सरकार ने निर्देश दिया है वे अनुदान समितियां सभी राज्यों में आपके निर्देश के अनुसार तीन महीने में एक बैठक करने का जो नियम है उसके हिसाब से कार्यवाही कर रही हैं या नहीं।

श्री रबी राय : सभापति महोदय, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग राज्य सरकार के जरिये वालियेन्टरली संस्थाओं को अनुदान देते हैं और यह भी मैं सदन के खिदमत के लिये बता देना चाहता हूं कि पहले यह था कि एक लाख रुपया दिया जाता था पर अब यह राशि बढ़ाकर ढाई लाख तक राज्य सरकारों के जरिये देते हैं और ढाई लाख से ज्यादा हम केन्द्रीय सरकार की ओर से देते हैं। दूसरा जो माननीय सदस्य का सवाल था कि कौन-कौन संस्थायें है जिनके बारे में शिकायतें है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में आल इंडिया प्राइमरी टीचर्स एसोसियेशन पटना, उनकी कुछ शिकायत है। इसके बारे में हमने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद हम उनको दे देंगे। तमिलनाडु में युनाइटेड प्लांट एसोसियेशन तमिलनाडु, मदुराई कोआपरेटिव एसोसियेशन मदुराई, मद्रास कोआपरेटिव्स मद्रास, तमिलनाडु में ही गांधी ग्राम इन्स्टीट्यूट आफ रूरल हेल्थ एण्ड फेमिली प्लानिंग, मारी म्युनिसिपैलिटीज, महाराष्ट्र में फेमिली प्लानिंग एसोसियेशन आफ बम्बई, यू० पी० में नगर महापालिका वाराणसी, आन्ध्र प्रदेश में भारतीय महिला ग्रामीण संघ, गुजरात में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, इनके मामले पेंडिंग हैं। हम लोगों ने इनके बारे में कुछ सूचनायें मांगी हैं। सूचना आ जाने के बाद हम उनको रिलीज कर देंगे।

श्री किशन लाल शर्मा: श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके निर्देश के अनुसार उन अनुदान समितियों की बैठकें बराबर हो रही हैं अथवा नहीं ?

श्री रबी राय : सभापति महोदय, हम लोगों ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे राज्य

तरीय ग्रांट्स समिति बनायें, यदि हो सके में। जिला स्तरीय ग्राम समितियां भी बनाई य । हमको इत्तिला मिली है कि राज्यों े ग्रांट्स कमेटियां बन चुकी हैं और वे राज्यों जच्छा काम कर रहे हैं ।

شری سید <u>نظام الدین</u> : میں منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاهتا هوں کہ ان کو کچھ پرائیویٹ انسٹی ٹیوشن کی طرف سے جو شکایتیں ملی هیں کہ ان کو گرانٹ نہیں ملی هے تو کیا اس میں کہیں بهی سیاسی وجہ سے کسی انسٹی ٹیوٹ کو گرانٹ نہیں دی گئی هے - کیا یہ بهی شکایت کہیں سے آئی هے - دوسری بات یہ هے کہ جو گرانٹ مل رهی هے وہ کوارٹرلی ملنی چاهئے - هر تین مہینے کے بعد ملنی چاهئے جو کہ گرانٹ ان رول هے - تو کیا جن لوگوں کو تین تین مہینے سے گرانٹ نہیں ملی هے اس کے بارے میں سنٹرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ گورنمنٹ سے رپورٹ لی هے کہ آپ لوگوں نے گرانٹ تین مہینے کے بعد کیوں تقسیم نہیں کی هے - اگر آپ نے ایسی رپورٹ نہیں مانگی هے تو کیا آئیندہ آپ ایسی رپورٹ مانگا کرینگے تاکہ یہ پتہ چلے کہ گرانٹ ان ایڈ جن کو آپ نے ڈی سینٹرلائز کرکے بہت اچھا کام کیا هے اس کو سیاسی طور پر اسٹیٹ گورنمنٹ استعمال نہ کرے اس لئے کیا سرکار کوئی کاروائی کرنے جا رهی هے -

†[श्री सैयद निजामुद्दीन : मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि उनको कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो शिकायतें मिली हैं इनको ग्रांट नहीं मिली तो क्या इसमें कहीं भी सियासी वजह से किसी इंस्टीट्यूट को ग्रांट नहीं दी गई है । क्या यह भी शिकायत कहीं से आई है ? दूसरी बात यह है कि जो ग्रान्ट मिल रही है वह क्वार्टरली मिलनी चाहिए । हर तीन महीने के बाद मिलनी चाहिए जोकि ग्रान्ट-इन-एड का रूल है । तो क्या जिन लोगों को तीन-तीन महीने से ग्रान्ट नहीं मिली है उसके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली है कि आप लोगों ने ग्रान्ट 3 महीने के बाद क्यों तकसीम नहीं की है अगर आपने ऐसी रिपोर्ट नहीं मांगी है तो क्या आइन्दा आप ऐसी रिपोर्ट मांगा करेंगे ताकि यह पता चले कि ग्रान्ट-इन-एड जिनको आपने डीसेन्ट्रालाइज करके बहुत अच्छा काम किया है । इसको सियासी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट इस्तेमाल न करे इसके लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?]

श्री रवी राय : सभापति महोदय, निजामुद्दीन जी का जो सवाल है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वच्छिक संस्थाओं के जरिये परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये हम पहले जितने रिजिड थे उसमें अब हम बहुत लिबरल हो गये हैं और हमने राज्य सरकारों को भी कहा है कि वे भी रिजिड न बनें, लिबरल बनें । इस सम्बन्ध में हमारे आफिसर भिन्न-भिन्न राज्यों में जायेंगे । जहां तक सियासी तौर पर ग्रान्ट न दिये जाने का प्रश्न है, मैं निजामुद्दीन साहब को कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा कोई मामला है तो वह हमें बता दें, सरकार उस बारे में दरियाफ्त करने को तैयार है ।

---

†[ ] Devanagari translation.

PROF. RAMLAL PARIKH: Sir, while discussing the problem of family planning it would be important to know what has been the impact of the grants that have been paid to the voluntary agencies so far because it is very much essential to find out whether the Government have really attempted to enlist extensive co-operation of the voluntary agencies. Sir, the magnitude of the problem is becoming graver and graver. Perhaps, we might even miss our target, a particular target fixed for 1982. The population explosion would then be uncontrollable. Is the Government thinking seriously to widen its network of enlisting the cooperation of voluntary agencies and local bodies, Members of Parliament, members of legislature in this effort, or it just wants to depend on bureaucratic mechanism only?

श्री रबी राय : सभापति महोदय, मैं पारिख जी के साथ पूरा सहमत हूं कि इस परिवार नियोजन कार्यक्रम में सारी जनता का सहयोग होना चाहिए । यही हमने अपने पालिसी स्टेटमेंट में भी कहा है इसलिये हम स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेंगे और मैं उनको यह बता दूं कि यह सही है कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में इन स्वैच्छिक संस्थाओं को काम करना चाहिए वह अभी नहीं कर रही हैं। अभी जितने इलाकों में मैंने जो दरियाफ्त किया तो हमें यह पता चला कि यह शहर में ही सीमित है । गांधी ग्राम इंस्टीट्यूट जो मद्रास में है, वह ग्रामीण इलाकों में बहुत अच्छा काम कर रहा है । इस तरह के काम को ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने के लिए मैं कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं की नये सिरे से सूची मंगाऊंगा इसलिए मैं पारिख साहब और सारे सदस्यों से चाहूंगा कि वे इस तरह की संस्थाओं का नाम मुझे दे दें तो आगे चलकर मै उनका एक सम्मेलन बुलाकर इन ग्रामीण इलाकों में यह काम कैसे हो सकता है, इसको देखूंगा ।

SHRI B. N. BANERJEE: I would like the hon. Minister to let me know what sum of money Government of India proposes to spend during the current financial year on the family welfare programmes, what percentage of that money is proposed to be spent by the Government through its own agencies. Secondly, how far...

MR. CHAIRMAN: Now, no "secondly".

SHRI B. N. BANERJEE: It is the same question. What is the percentage through the agency of the State Governments and what is the percentage through the agency of the private institutions? What is the machinery available or being utilised by the Government for the purpose of seeing that the grants given to the State Governments or the private institutions are properly utilised?

श्री रबी राय : सभापति महोदय, इसके बारे में तो मैं सूचना चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में परसेंटेज देने का सवाल है । लेकिन अंतिम जो सवाल था इसके बारे मे कह दूं कि हम राज्य सरकार के जरिये ग्रांट देते हैं । मैं यह भी कह चुका हूं कि हम अढ़ाई लाख के ऊपर ग्रांट देते हैं । केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकारों के जरिये ग्रांट अढ़ाई लाख तक का है । इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ सहयोग से किस तरह से फीड बैक हो काम हो, वह कर रहे हैं । आगे चलकर मैं यह सुझाव याद रखूंगा ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : श्रीमन, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे स्थिति और अस्पष्ट हो गयी है उसका कारण यह है कि आपने यह बतलाया कि कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं को

सहायता दी जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वैच्छिक संस्थाओं को मदद दी जाती है, तो उन स्वैच्छिक संस्थाओं से आपका अर्थ क्या है, वे शैक्षणिक, सामाजिक या आर्थिक हैं, क्या हैं । वह रजिस्टर्ड हों और इसके बारे में जो ग्रांट इन एड पूरी व्यय होती है क्या वह पूरी रकम आप देते हैं या उसका परसेंटेज देते है और इसके बारे में कोई नियम केन्द्रीय शासन ने निर्धारित किये हैं अगर किये हैं तो उन नियमों की जानकारी क्या आप सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री रबी राय : सभापति महोदय, सिसोदिया जी ने जो प्रश्न किया मैं उसके अनुसार उनकी खिदमत में जबाब देना चाहता हूं कि:

In order to be eligible for financial assistance under the Family Welfare Programme, an institution|organisation should meet the following conditions:

(a) It should be registered body under Societies Registration Act, 1860 or any other statute or an institution of all-India character:

(b) It should be a non-official and under non-proprietory management;

(c) It should have a well defined objective to promote in the field of Family Welfare;

(d) It should be a non-profit organisation serving the general public without any distinction of caste or religion;

(e) It should have personal resources, experience and managerial ability to carry out the purpose for which the grant-in-aid is applied for;

(f) It should agree to furnish periodical reports|annual statement of accounts duly countersigned by any officer authorised by State Government or Government of India;

(g) It should agree to allow authorised officers to visit and inspect the accounts and general working of the institution;

(h) It should agree to consider and abide by the suggestions from the State Government|Ministry of Health and Family Welfare and to follow directives in respect of working of the institution.

अन्त मे मैं सिसोदिया जी से कहना चाहता हूं कि हम इसको और लिबरलाईज करने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार को कहते हैं कि इसके बारे में आप रिजिड मत हो ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : आप यह जानकारी पटल पर रखिए ।

श्री रबी राय : मैं रख रहा हूं ।

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA: I think the seriousness of the situation has been realised by the Government when I hear the hon. Minister answering these questions and also Prof. Parikh and other Members referring to this. But my question is slightly different. So far as the financial aid is concerned, he has answered the question. But I understand that there are certain private institutions or clinics who are prepared to do specialised work in this line and they would like specialised, sophisticated equipment to be supplied to them. I also understand that the Department or the Ministry has been refusing the supply of such euipment to some private institutions, clinics etc. who want to do this sophisticated work. I would like to have an assurance from the Minister that in genuine cases he would consider supplying sophisticated equipment for primary family planning

and other institutions. I have received some complaints about it.

SHRI RABI RAY: Please give in writing so that I can act.

MR. CHAIRMAN: Mr. Kulkarni. Are you particular about putting a supplementary?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: No.

U.S. Warships in the Indian Ocean

*64. SHRI JAGJIT SINGH ANAND:†
SHRI F. M. KHAN:
DR. BHAI MAHAVIR:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of U.S.A. have recently decided to increase the number of their warships in the Indian Ocean; and

(b) if so, what steps Government have taken in this regard and what are the names of the other nations who have raised their voice to ensure that the Indian Ocean remains a zone of peace?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) The Government of India is not aware of any recent decision on the part of the USA to increase the number of its warships in the Indian Ocean. We have also not received any information which would indicate an abnormal increase in the military presence of the US in the Indian Ocean.

(b) Government has been in touch with a number of non-aligned and friendly countries on this question. A conference of littoral and hinterland States and such other countries as may be interested is likely to be held towards the middle of this year under U.N. auspices.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagjit Singh Anand.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, first of all, I am very surprised at the answer given because when the situation in Iran became disfavourable to the U.S. Government it was in the entire press that right from the end of November itself and throughout December the U.S. Government was shifting its Flotilla and showing its flag within the Persian Gulf area which is very much a part of the Indian Ocean. After that it is a question of military build up in the Indian Ocean area specially in the adjoining countries. Now, President Carter himself has said three days back that after the collapse of his stooges in Iran, military equipment is being shifted to other areas. It is also known that sensitive equipment cannot be directly on the ocean itself. The hon'ble Minister should be aware that America itself claimed that its Flotilla is moving. He has not agreed to it. The whole area, the littoral States are being....

MR. CHAIRMAN: Please put your supplementary now.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Is he aware that the American Government itself, after the situation deteriorated there, claimed that the American ships are being shifted elsewhere? That is my first question.

MR. CHAIRMAN: That will do.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: I will ask the second question again.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: We are discussing the Indian Ocean. There were some reports about the American Navy or some of the warships belonging to the American Navy being moved to the Gulf. But that did not happen.

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, it is only in reply to my supplementary that he said that there were reports of American Naval ships being moved to the Gulf. They may not have reached the Gulf. It was clearly there in the Press that from the Pacific Ocean and from the Atlantic side the